

जम्मू-कश्मीर: भारत की अखंडता, सामरिक गहराई और भू-राजनीतिक शक्ति का बहुआयामी विश्लेषण

डॉ. सचिन तिवारी

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश), भारत

researchcell@gyanveeruniversity.edu.in

सारांश:

यह शोध-पत्र जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक, सामरिक, संवैधानिक और आर्थिक आयामों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में हृदय स्थल सिद्धांत, जल-राजनीति, चीन-पाकिस्तान कारक, तथा 2019 के बाद के प्रशासनिक और विकासात्मक परिवर्तनों का मूल्यांकन किया गया है। जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और सभ्यतागत निरंतरता का केंद्रीय स्तंभ है।

मुख्य शब्द : जम्मू-कश्मीर, अनुच्छेद 370, भू-राजनीति, CPEC, जल-राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा

प्रस्तावना

जम्मू-कश्मीर – भारत की अखंडता और सामरिक चेतना का केंद्र 'देवात्मा' हिमालय का मुकुट

भारतीय वांग्मय में हिमालय को 'देवात्मा' कहा गया है, और उसी का मुकुट है जम्मू-कश्मीर। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक है।

कल्हण की राजतरंगिणी से लेकर शारदा पीठ और अभिनवगुप्त के दर्शन तक, कश्मीर भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है। अतः इसका महत्व 1947 से नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों से स्थापित है।

सामरिक गहराई और 'हृदय स्थल'

जम्मू-कश्मीर एशिया के उस रणनीतिक चौराहे पर स्थित है जहाँ दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशिया का संगम होता है। भारत के लिए यह क्षेत्र केवल सीमांत नहीं, बल्कि रणनीतिक गहराई प्रदान करने वाला सुरक्षा कवच है।

मैकिन्डर के अनुसार, यूरेशिया का नियंत्रण वैश्विक शक्ति संतुलन निर्धारित करता है। भारतीय दृष्टिकोण से, कश्मीर इस क्षेत्र तक पहुँच का द्वार है।

यह भारत की महाद्वीपीय रणनीति को सुदृढ़ करता है और मध्य एशिया से जुड़ाव सुनिश्चित करता है।

- **रणनीतिक गहराई और राष्ट्रीय सुरक्षा**

जम्मू-कश्मीर भारत की राजधानी और उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

इसकी ऊँचाइयाँ और भू-आकृति संभावित शत्रु आक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा तंत्र निर्मित करती हैं।

- **काराकोरम, अक्साई चिन और शक्ति संतुलन**

यह क्षेत्र चीन और पाकिस्तान के बीच सामरिक संपर्क का केंद्र है।

सियाचिन पर भारत का नियंत्रण एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि है, जो दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को सीमित करता है।

- **यूरेशियाई कनेक्टिविटी और नीति आयाम**

भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति का आधार जम्मू-कश्मीर की स्थिरता है।

यह क्षेत्र ऊर्जा, व्यापार और सामरिक सहयोग के नए अवसर प्रदान करता है।

सीमा अवसंरचना, स्मार्ट निगरानी और रणनीतिक मार्गों के विकास ने इस क्षेत्र की सामरिक क्षमता को अत्यधिक बढ़ाया है।

अनुच्छेद 370 का उन्मूलन:संवैधानिक एकीकरण

2019 में अनुच्छेद 370 और 35A का निष्प्रभावी होना भारत की संवैधानिक एकता को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम था।

यह परिवर्तन प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक एकीकरण का भी प्रतीक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संप्रभुता का आधार: एक विधिक एवं सामरिक विश्लेषण

जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय केवल एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की 'सभ्यतागत निरंतरता' (Civilizational Continuity) को राजनीतिक मान्यता देने का एक वैधानिक उपक्रम था। इस क्षेत्र की संप्रभुता निर्विवाद और पूर्ण है।

विलय पत्र की वैधानिकता

26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित 'विलय पत्र' वही कानूनी दस्तावेज था जिसके आधार पर अन्य 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय हुआ था।

अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ सी.एच. अलेक्जेंड्रोविच ने स्पष्ट किया है कि भारत में राज्यों का विलय 'बिना किसी शर्त' के था। भारतीय न्यायविद एम.सी. छागला ने 1964 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐतिहासिक वक्तव्य देते हुए कहा था, "कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है क्योंकि यह भारत की आत्मा का हिस्सा है, न कि केवल कागजी कार्रवाई का।"

संसदीय संकल्प (1994): 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर (जिसमें पाक-अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान शामिल हैं) भारत का हिस्सा है और रहेगा। 2026 के भारत की विदेश नीति इसी संकल्प को 'शक्ति' (Hard Power) के साथ दोहराती है।

सभ्यतागत और सांस्कृतिक जुड़ाव: 'ऋषि कश्यप की भूमि'

भारतीयता के दृष्टिकोण से, कश्मीर का इतिहास 1947 से नहीं, बल्कि सतयुग से प्रारंभ होता है।

शारदा पीठ और ज्ञान परंपरा: प्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन के अनुसार, कश्मीर सदियों तक 'शारदा देश' के रूप में जाना जाता था, जो भारतीय मेधा और संस्कृत विद्वत्ता का केंद्र था। आदि शंकराचार्य का कश्मीर आगमन और वहाँ 'सर्वज्ञ पीठ' पर विराजमान होना यह सिद्ध करता है कि कश्मीर दक्षिण से उत्तर तक भारत की सांस्कृतिक एकता का सूत्र रहा है।

लल्लेश्वरी और सूफी-संत परंपरा: कश्मीर की धरती ने 'लल घद' और 'नंद ऋषि' जैसे संतों को जन्म दिया, जिन्होंने शैव दर्शन और सूफीवाद के समन्वय से 'कश्मीरियत' की रचना की, जो मूलतः भारतीय समावेशी विचारधारा का ही विस्तार है।

सैन्य भूगोल: 'सामरिक ऊँचाई'

सैन्य विशेषज्ञों और जनरल वी.के. सिंह जैसे रणनीतिकारों ने अपनी चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया है कि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक बनावट भारत को सैन्य लाभ प्रदान करती है यह क्षेत्र भारत के विशाल मैदानों (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली) के लिए एक प्राकृतिक रक्षा प्राचीर है।

काराकोरम और सिल्क रोड: ऐतिहासिक रूप से, कश्मीर का वह मार्ग था जिससे भारत का व्यापार 'सिल्क रोड' के माध्यम से रोम और चीन तक पहुँचता था।

गिलगित-बाल्टिस्तान:

विद्वान आलोक बंसल ने अपनी पुस्तक 'Gilgit-Baltistan: The Northern Gate' में तर्क दिया है कि भारत की सुरक्षा के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान का सामरिक महत्व सर्वोपरि है।

चीन-पाक गठजोड़: गिलगित-बाल्टिस्तान वह क्षेत्र है जहाँ चीन (अक्साई चिन) और पाकिस्तान (पीओके) की सीमाएं मिलती हैं। भारत के लिए यह 'दोहरे खतरे' (Collusive Threat) का केंद्र है।

2025 का परिदृश्य: भारत सरकार ने 2025 तक लद्दाख में जो 'न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर' विकसित किया है, वह गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत के नैतिक और कानूनी दावे को और अधिक मुखर करता है।

सरकारी आंकड़े और सुरक्षा संरचना (2024-2025)

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (MoD) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक एकीकरण (Civil-Military Integration) के नए मॉडल अपनाए गए हैं:

जल-राजनीति: संसाधन और रणनीतिक नियंत्रण

जम्मू-कश्मीर दक्षिण एशिया का 'वॉटर टावर' है। सिंधु नदी प्रणाली भारत को सामरिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है।

भारत जल-विद्युत क्षमता के विस्तार और संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है। विद्वानों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जल के ऊपर से भी अगला बार हो सकता है जैसे कि हमको मालूम है कुछ नदियां चीनी क्षेत्र या तिब्बत से होते हुए भारत में आती हैं और इस पर भी कुछ चीन द्वारा डेम का निर्माण किया जा रहा है भारत ने भी पाकिस्तान के साथ इस चीज पर ध्यान दिया है कि हमारे क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियों का जल की स्थिति क्या है और भारतीय क्षेत्र में

इसका कितना उपयोग हो रहा है पाकिस्तान द्वारा जल का दुरुपयोग या कोई समझौते का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

CPEC और चीन-पाकिस्तान कारक

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। 62 अरब डॉलर से अधिक की यह चीन और पाकिस्तान के द्वारा द्विपक्षीय योजना है जो चीन के चिन्हांग प्रांत से होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है इसके माध्यम से पाकिस्तान की ऊर्जा के संकट को दूर करना होगा पाकिस्तान में आधारभूत ढांचा तैयार करना

यह परियोजना गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है, जिससे भारत की सामरिक चिंताएँ बढ़ती हैं। 2015 में शुरू की गई योजना पाकिस्तान को आर्थिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करेगी भारत इस परियोजना का विरोध करता है क्योंकि यह pok से होकर गुजरती हो भारत से अपना अंग मानता है

भारत ने इसके उत्तर में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियाँ विकसित की हैं।

आंतरिक शासन और विकास: 'नया कश्मीर' (2019-2025)

लोकतांत्रिक पुनर्स्थापन

2024 के चुनावों में उच्च मतदान लोकतंत्र में जनता विश्वास को दर्शाता है।

कश्मीर में धारा 370 के खत्म होने के बाद यह पहला चुनाव था इसलिए सारी दुनिया की निगाहें कश्मीर की इस राजनीतिक घटना पर टिकी हुई थी भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र होने स्वच्छ चुनाव कराने में पूर्व से सफल हुआ इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस बाय 42 सीटों के सॉन सबसे बड़ी पार्टी ऊपरी एवं भाजपा को 29 सिम प्राप्त हुई कांग्रेस को 6 प्राप्त हुई। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी इस प्रकार घाटी में एक सदस्य सरकार स्थापित हुई जो भारत की मजबूत लोकतंत्र प्रणाली और भारत की लोकतांत्रिक निष्पक्षता को दर्शाती है

सुशासन और डिजिटलीकरण

ई-गवर्नेंस और पंचायत सशक्तिकरण से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है। 2019 के बाद सरकार ने पूरी घाटी को जम्मू कश्मीर को ई गवर्नेंस और पंचायती राज की मजबूत करने की तरफ जोर दिया डाटा सेंटर की स्थापना एवं डिजिटल राशन योजना के तहत जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कारभार सरकार की

तरफ से प्रारंभ किया गया इससे आम जनमानस में एक विश्वास एवं निष्पक्षता और प्रदर्शित भी स्थापित हुई

आर्थिक विकास

निवेश, पर्यटन और कृषि (जैसे लेवेंडर मिशन) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों की आंखों पर अगर हम ध्यान दें तो लगातार घाटी में लोगों का विश्वास पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है ऑपरेशन तंत्र मजबूती से कम कर रहा है जिसका परिणाम हुआ की घाटी में खेलों की गतिविधियां पर्यटन को बढ़ावा देने वाली लोगों को वहां जाने के लिए सुविधा प्राप्त हुई लैवेंडर मिशन भारत की सरकार की एक भाभी योजना है जिस पर सरकार ने कुछ बजट भी रिलीज किया है और घाटी में उसके प्रति उत्साह भी जागृत हुआ है।

अवसंरचना विकास

रेलवे, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। जम्मू कश्मीर को और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रेल की लाइनों का अधिक से अधिक बढ़ावा देना और उसके यात्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है एवं सरकार द्वारा उसके द्वारा अधिक से अधिक बजट देने का प्रावधान किया गया है यह सब रोजगार को बढ़ावा देता है एवं उसके साथ-साथ वहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है

सुरक्षा परिदृश्य में परिवर्तन

आतंकवाद और पत्थरबाजी में कमी आई है, जिससे स्थिरता बढ़ी है। धारा 370 की समाप्ति के बाद योजना जम्मू कश्मीर के युवाओं में एक उत्साह है उनका रोजगार की में वृद्धि हुई है एवं जो आधारभूत संरचना तैयार की गई है एवं नए उद्योगों को लगाने के लिए भी उन्हें आकर्षण पैदा हुआ है इससे लगातार यह आंकड़ा भी देखने में आया है की घाटी में पत्थर बाजी की घटनाओं में निरंतर कमी आई है लगातार भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की युवाओं के अंदर कोचिंग सेंटर बढ़ावा देने जिससे सरकार की योजना में यह छात्र आगे भारत सरकार की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित हूं अभी कुछ समय देखने में आया कि जम्मू कश्मीर के साथ छात्राओं द्वारा यूपीएससी जैसे बड़े परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की है गणपति भगवान खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में भी भागीदारी की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती जो घाटी से दूरी थी उसको खत्म करके उसकी

जरूरत के मुताबिक सारे काम किया जा रहे हैं जैसे उसमें युवाओं के अंदर यह महसूस हो कि हमें पर रोजगार के अवसर है पर्यटन के अवसर है एवं हमको जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देना है।

निष्कर्ष

इस शोध से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर भारत के लिए केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का केंद्र है।

2019 के बाद के परिवर्तनों ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है, जहाँ सुरक्षा और विकास साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं।

भविष्य में, यह क्षेत्र भारत की वैश्विक रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव का प्रमुख आधार बना रहेगा।

संदर्भ

1. भारत सरकार (एमएचए/एमओडी): वार्षिक सुरक्षा एवं विकास रिपोर्ट 2025-26।
2. चेलानी, ब्रह्मा: जल: एशिया का नया युद्धक्षेत्र, 2024 संस्करण।
3. राजा मोहन, सी.: दक्षिण एशिया की भू-राजनीति, शोध पत्र (ओआरएफ 2025)।
4. भारतीय निर्वाचन आयोग: 2024 विधानसभा चुनाव परिणाम एवं डेटा रिपोर्ट।
5. नीति आयोग: जम्मू और कश्मीर बुनियादी ढांचा विकास रिपोर्ट 2026।
6. मैककिंडर, एच.: इतिहास की भौगोलिक धुरी (ऐतिहासिक संदर्भ अनुभाग)।